

नकली खरपतवार नाशक दवा से 15 एकड़ फसल बर्बाद

प्रदेश में नकली कीटनाशक दवाओं की दुकान खुलेआम चल रही

नवभारत प्रतिनिधि
भोपाल, 20 अगस्त. कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कुछ दिन पहले नकली कीटनाशक और खरपतवार दवाओं को लेकर जाली दुकानदारों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसका कोई असर जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है. प्रदेश में नकली कीटनाशक दवाओं की दुकान खुलेआम चल रही हैं. जिसकी मार आम किसान खा रहा है. कड़ी मेहनत से किसान एक तरफ किसान फसलों को उपजाते हैं और दूसरी तरफ नकली खरपतवार, कीटनाशक दवाओं से



फसल बर्बाद हो रही है. प्रदेश के कई जिलों से लगातार खरपतवार और कीटनाशक दवाओं की शिकायत कृषि मंत्री तक पहुंच रही थी. जब किसान की फसल

खरपतवार नाशक दवाई डालने से पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो वह कहाँ जाए. किससे गुहार लगाए. ताजा मामला रायसेन जिले के सिलवानी तहसील बूढ़ा गांव का

सामने आया है. किसान सत्यम कौरव ने बताया कि उन्होंने अपने 15 एकड़ के खेत में तुअर की दाल लगाई थी. जिसमें खरपतवार नाशक दवा रेवा कृषि निदान उदापुरा से खरीदी थी. उसके छिड़काव के 24 घंटे बाद ही फसल 50 प्रतिशत तक खराब हो गई. कुछ ही दिन में पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी सुनवाई के लिए मैंने टाटा कंपनी के टीएम अजय सिंह और रचित रघुवंशी को अवागत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई परीक्षण या जांच नहीं की. इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को इस विषय में

जानकारी दी. जिसके बाद केंद्र और जिला दोनों ही स्तर से टीमें आई और परीक्षण किया.

कृषि विभाग टीम के परीक्षण अनुसार उन्होंने बताया कि यह खरपतवार नाशक दवा तुअर की फसल के लिए नहीं बल्कि सोयाबीन और अन्य फसलों के लिए है. जिसकी वजह से फसल को पूर्ण रूप से नष्ट हो गई. फिलहाल परीक्षण के बाद विभाग की कार्यवाही अनुसार दुकानदार संचालक राजेंद्र रघुवंशी का लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित कर दुकान को सील कर दिया है.

प्रदेश के कई जिलों में नकली कीटनाशक से जुड़ी शिकायतें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह वहां तक पहुंचने के बाद कृषि विभाग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. वलोरिम्यूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के उपयोग से सोयाबीन की फसलें खराब हो गई हैं. शिकायत के बाद कृषि विभाग ने कार्रवाई की और बाजार से खरपतवार नाशक के सैपल लेकर जांच की गई. जांच में हर्बिसाइड के नमूने घटिया पाए गए. 3 जिलों विदिशा, देवास और धार में डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

ग्वालियर हाईकोर्ट की फटकार

कामचोरों को बाहर करें नगर निगम

ग्वालियर, 20 अगस्त. शहर की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई.

इस दौरान कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि ग्वालियर को इंदौर की तरह स्वच्छ शहर बनाना है, तो सफाई व्यवस्था में लापरवाही करने वाले कामचोर कर्मचारियों को बाहर करना होगा. इससे सख्त संदेश जाएगा और व्यवस्था बेहतर होगी. नाशक के सैपल लेकर जांच की गई. जांच में हर्बिसाइड के नमूने घटिया पाए गए. 3 जिलों विदिशा, देवास और धार में डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

और नालों की सफाई में लापरवाही के कारण स्थिति बिगड़ गई है. न्याय मित्र ने कोर्ट में यह मुद्दा उठाया, जिस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को कड़ा रख अपनाने को कहा.

नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में लापरवाह सफाईकर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है. पिछले दो महीनों में 20 से अधिक सफाईकर्मियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं. साथ ही सतत मॉनिटरिंग की जा रही है. निगमायुक्त ने कहा कि अब डब्ल्यूएचओ और पावर्टी के साथ बैठक कर सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने की रणनीति तय की जाएगी.

एक नजर में
जमीन का सौदा, पैसा हड़पने का आरोप

उमरिया. करकेली जनपद अध्यक्ष के पति मून सिंह पर जमीन के सौदे में करोड़ों रुपये हड़पने और वृद्ध किसान को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. 82 वर्षीय जगन्नाथ शुक्ला ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जमीन 2021 में 95 लाख रुपये में मून सिंह को बेची थी. जमीन की रजिस्ट्री होने के बावजूद चार साल बाद भी उन्हें शेष 72 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान नहीं मिला. पैसे की मांग करने पर आरोपी द्वारा जान से मारने और परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है. शुक्ला का कहना है कि उन पर एससी-एसटी एक्ट लागू करने की चेतावनी दी जाती है.

रेलवे को 4 माह में 1953 करोड़ का राजस्व मिला

भोपाल. पम्परे ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह तक कई कर्मोडिटी लोडिंग में बेहतर लोडिंग की है. पम्परे ने चालू वित्तीय वर्ष में गुड्स ट्रेफिक में 18.74 मिलियन टन फ्रंट लोडिंग की और 1953 करोड़ 07 लाख रुपये राजस्व अर्जित किया है. इसी अवधि में पिछले वर्ष से तुलना करने पर गुड्स ट्रेफिक में लगभग 07 प्रतिशत फ्रंट लोडिंग और रेल राजस्व में लगभग 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. रेलवे ने फूडग्रेन लोडिंग में 0.1.30 मिलियन टन माल लदान किया जो पिछले वर्ष 0.0.98 मिलियन टन माल लदान की तुलना में 33.18 प्रतिशत अधिक है. कोल लोडिंग में 0.4.67 मिलियन टन माल लदान किया जो पिछले वर्ष 0.3.92 मिलियन टन माल लदान की तुलना में 19.27 प्रतिशत अधिक है.

अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ खूनी खत

भोपाल, 20 अगस्त. मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 71 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद संगठन के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है.

भोपाल कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष प्रदीप 'मोनु' सक्सेना ने मंगलवार को बिट्टन मार्केट स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने खून से पत्र लिखकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से न्याय की मांग की और मौजूदा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए. सक्सेना ने भोपाल के नव नियुक्त शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना की नियुक्ति को लेन-देन का परिणाम बताया और आरोप लगाया कि उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी नेताओं से भी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि



न्याय नहीं मिला तो वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी के सामने आत्मदाह

पूर्व में भी सक्सेना ने आरोप लगाया था कि शहर अध्यक्ष का पद पाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की डिफेंडर कार गिफ्ट की गई है. उन्होंने जल्द ही इसके प्रमाण सार्वजनिक करने की बात कही है. उधर, 24 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नव नियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली बैठक लेंगे, जिसमें संगठन को मजबूत करने की रूपरेखा बताई जाएगी.

करने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि वे वर्षों से संगठन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता राहुल गांधी को अंधेरे में रखकर व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों को संगठन में पद दिलवा रहे हैं. इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन को आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी.

हिंदी को पुनः प्रतिष्ठित करने में चतुर्वेदी की भूमिका

भोपाल, 20 अगस्त. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कहा कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी को पुनः प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाई और वे राज्य के लिए गर्व की बात है कि

उनका जन्म मध्यप्रदेश में हुआ. डॉ यादव ने यहां स्थित माखनलाल चतुर्वेदी विश्व विद्यालय में तीन दिवसीय अभ्युदय-2025 का उद्घाटन कर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण किया.

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, कवि डॉ कुमार

डॉ यादव ने कहा कि देवर्षि नारद को पत्रकारिता का आद्य प्रवर्तक माना जाता है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 'अभ्युदय' का अर्थ मात्र आरंभ नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता, सत्य की खोज और समाज को नई दिशा देने वाले उतरदायित्व की यात्रा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रत्येक पूर्व हमें कोई न कोई संदेश देते हैं. दशहरा का पूर्व पुरुषार्थ का संदेश देता है और यह बात माखन दादा से भी जुड़ती है. उन्होंने पत्रकार रहते हुए देश और समाज के हित के लिए आंदोलन का भी रास्ता अपनाया.

विश्वास और विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी उपस्थित रहे. समारोह को संबोधित करते हुए डॉ यादव ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पूरे देश में विशिष्ट पहचान है. पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी भाषा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण अभियान

चलाया. हमें गर्व है कि ऐसे महापुरुष और महान कवि का जन्म मध्यप्रदेश की धरती पर हुआ. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में सरकार ने कुलपति के स्थान पर 'कुलगुरु' शब्द के प्रयोग की परंपरा प्रारंभ की. यह हमारी शिक्षा परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान देने का प्रतीक है.

अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की कहानी से उठा पर्दा

सारांश के साथ तेजेंद्र को खेल में किया था शामिल



नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 20 अगस्त. कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी को जीआरपी भोपाल ने नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी (उप्र) से बरामद किया. बुधवार को एसपी राहुल लोढ़ा

ने पिछले कई दिनों से लापता हुई अर्चना की कहानी से पर्दा उठाया. लोढ़ा के अनुसार अर्चना ने पुलिस को अपनी मिसिंग स्टोरी को लेकर बताया कि वह ग्वालियर में पदस्थ कॉन्स्टेबल राम सिंह तोमर के फोन काल और मैसेज से लगातार परेशान

सर्विग में संदेह के तौर पर नाम सामने आया

जीआरपी की सर्विग में संदेह के तौर पर सारांश का नाम सामने आने के बाद उससे पूछताछ की गई. इसके बाद अर्चना से संपर्क किया और घटना का खुलासा हुआ. पूछताछ में अर्चना तिवारी ने बताया कि मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए शादी के रिश्ते देख रहे थे. कुछ दिन पहले मेरे घरवालों द्वारा बताया गया कि तुम्हारे रिश्ते के लिये एक पटवारी लड़का देखा है. अर्चना के अनुसार घरवाले शादी के लिए उसे मजबूर कर रहे थे. जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान थी. इसीलिए उसने अपनी गुमशुदगी का खेल रचा.

थी. कॉन्स्टेबल तोमर उसे लगातार कॉल कर परेशान करता था, दोनों की दोस्ती जबलपुर में हुई थी. इंदौर में अर्चना की दोस्ती शुजालपुर रहवासी सारांश जोगचंद्र से हुई थी. अर्चना ने ही अपने गुमशुदा होने की कहानी खुद ही गढ़ी थी, जिसमें

वीडियों कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बिंदुओं पर हुई चर्चा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 20 अगस्त. राज्य के उद्योग तथा व्यवसायों के लिए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों एवं औद्योगिक स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के परिपालन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन करने वाले प्रबंधन हेतु श्रम स्टार रेटिंग की परिकल्पना की गई है. गत दिवस राज्य के उद्योग तथा व्यवसायों के प्रतिष्ठित संगठनों तथा प्रबंधकों से वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संबंध में चर्चा की गई. श्रम विभाग के

सचिव रघुनारायण एम राजेन्द्र ने इस अवसर पर कहा कि सभी के सहयोग से श्रम सुरक्षा प्रावधानों का बेहतर परिपालन किया जायेगा. चर्चा के प्रारंभ में सचिव श्रम राजेन्द्र द्वारा प्रस्ताव की प्रारंभिक रूप रेखा प्रस्तुत की और श्रम आयुक्त ने इसकी आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डाला. श्रम स्टार रेटिंग की प्रस्तुति अपर श्रम आयुक्त प्रभात दुबे द्वारा की गयी. इस दौरान विभिन्न संगठनों तथा प्रबंधकों द्वारा एकमत से इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये. कहा गया कि सेल्फ असेसमेंट की प्रणाली में स्व-प्रकाश को प्रस्तावित वेटेज अधिक प्रतीत होता है.

लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों हेतु यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए. स्वतंत्र इम्पेनल्ड एजेंसियों का चयन उद्योगों तथा विभाग की सहमति से तय किया जाना उचित होगा. उच्च रेटिंग के आधार पर शासकीय क्रय में प्राथमिकता तथा शासन से सप्लायर और अन्य इन्वॉयट मिलना चाहिए. श्रम कानूनों के किन प्रावधानों को सम्मिलित किया जायेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए. अन्य प्रस्तावित मापदण्डों में भी सुस्पष्ट विवरण हो. रेटिंग जारी होने के बाद प्रशासकीय होने की समय-सीमा नियत हो और रेटिंग कितनी समय अवधि में होगी इसकी प्रीक्लिंसी तय हो.

सेफ्टी, क्राउड मैनेजमेंट पर पर फोकस

महाप्रबंधक ने की संरक्षा की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 20 अगस्त. पम्परे महा प्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में बुधवार को-आडिनेशन रिस्क् मीटिंग संपन्न हुई. बैठक में सेफ्टी, क्राउड मैनेजमेंट, रेलगाडियों के संरक्षित एवं सुरक्षित परिचालन पर जोर देने पर बात हुई. इसके साथ ही प्रमुखता से ल्योहारां पर रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया एवं प्लेटफार्मों और ट्रेनों में क्राउड मैनेजमेंट और अन्य रेल सुविधाओं जैसे अनेक विषयों पर समीक्षा कर विचार-विमर्श किया गया. महाप्रबंधक ने कहा कि संरक्षा



पश्चिम मध्य रेलवे की प्राथमिकता हैं. उन्होंने ने संरक्षा एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने संरक्षा से सम्बंधित सुधारों को योजनाबद्ध तरीके से पालन करने हेतु निर्देशित किया. उन्होंने रेल पट्टियों की आंतरिक संरचना की सूक्ष्म जाँच के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन तकनीक से मॉनिटर

करना एवं टर्नआउट परीक्षण, ट्रेक परीक्षण, स्वीच इम्पेक्शन जॉइंट्स परीक्षण से संबंधित कार्यों के सेफ्टी पर जोर देने की बात कही. मीटिंग के दौरान महाप्रबंधक ने आने वाले त्योहारों पर आगामी महीनों में दशहरा, दीपावली एवं छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर यात्रियों को जवाबदा से ज्यादा रेल सुविधाओं का बेहतर लाभ सुनिश्चित किया जाय.

पितृपक्ष में सोगरिया-गया स्पेशल ट्रेन चलेगी

भोपाल. पितृपक्ष पर गया में पिंडदान और तर्पण करने जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. श्रद्धालुओं की यात्रा को देखते हुए रेल प्रशासन ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस सुविधा का लाभ भोपाल मंडल के यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि यह विशेष रूटियाई, गुना एवं अशोकनगर पर भी ठहरेगी. गाड़ी संख्या 09817 सोगरिया-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 6, 13 एवं 20 सितंबर को सोगरिया स्टेशन से रात 23:10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रविवार को रात 23:45 बजे गया स्टेशन पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 09818 गया-सोगरिया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 14 एवं 21 सितंबर को गया स्टेशन से रात्रि 01:15 बजे प्रस्थान कर मंगलवार को रात 01:10 बजे सोगरिया पहुंचेगी.

पीपीपी मोड से बनेगा मेडिकल कॉलेज : शुक्ल



भोपाल, 20 अगस्त. मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को कहा है कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है.

बैतूल जिले में 'पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप' मोड पर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. शुक्ल ने मंत्रालय में इस परियोजना की वृहद समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार

आरकेडीएफ समूह इस मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण अस्पताल को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के अनुरूप एक वर्ष में तैयार करेगा. विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और स्टाफ के लिए आवासीय परिसर भी निर्मित किए जाएंगे. शुक्ल ने अधिकारियों को शीघ्र भूमि आवंटन और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा.

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने स्टाफ, अत्याधुनिक उपकरणों और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा. बैठक में बैतूल से बढ़ाकर 675 बिस्तरों की जाएगी. 25 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित इस परियोजना में आधुनिक कैथलैब, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी सुविधाएं मिलेंगी. जिला अस्पताल का प्रशासन शासन के पास ही रहेगा, जबकि निजी भागीदारी से

विशेषज्ञ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, अत्याधुनिक उपकरणों और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा. बैठक में बैतूल विधायक हेमन्त खंडेलवाल, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चन्द्रशेखर देशमुख, प्रमुख सचिव संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी के तथा आरकेडीएफ समूह के चैथमैन डॉ. सुनील कुर्पूर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

परिवहन सुविधा बिना पैसे खर्च किए बसों चलाने की तैयारी में परिवहन विभाग, प्रक्रिया शुरू

पीपीपी मोड की लक्जरी बस में सफर करेंगे यात्री

कन्हैया लोधी
भोपाल, 20 अगस्त. पिछले दो दशक से भी अधिक समय से प्रदेश में सरकारी यात्री बसों की सुविधा का इंतजार की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं. प्रदेश में जल्द ही पीपीपी मोड पर यात्रियों को वाजिब किराए पर लक्जरी बसों में सफर करने का मौका मिलेगा. इससे किराये को लेकर प्रदेश में निजी ऑपरटर्स को मोनोपॉली पर धीरे से रोक लग जाएगी और फिर सड़कों पर सरकार के नियंत्रण वाले यात्री बसों का कब्जा होगा. परिवहन विभाग ने

इसके लिये पूरी तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत प्रदेश में इसी वर्ष यात्री बसों का संचालन शुरू हो जाएगा. इसके लिए प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनेगी, जिसे मप्र यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कहा जाएगा. इस होल्डिंग से सम्बंधित तहत 7 और सहायक कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों में होगी, जो बसों के संचालन और प्रबंधन को नियंत्रित करेंगी. इसकी शुरुआत उज्जैन से होगी. उज्जैन के अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में ये कंपनियां होगी.

अभी प्रदेश में सड़क परिवहन के लिए सरकारी सुविधा के अभाव में पूरा नियंत्रण निजी ऑपरटर्स का है. वर्ष 2005 में मप्र सड़क परिवहन विभाग के परिसमापन के बाद निजी ऑपरटर्स का दायरा लगातार बढ़ा है. ये भी प्रदेश के हैवी ट्रेफिक रूट में यात्री बसों का संचालन कर रहे हैं. ऐसे क्षेत्र जहां यात्रियों की संख्या कम है, उन क्षेत्रों में परिवहन के लिये लोकल वाहनों का ही सहारा है. इन बसों को परमिट राज्य सरकार देगी. सबसे बड़ी बात कि जिन रूट पर बसों का संचालन होगा, वहां अन्य बसों नहीं चलेगी. यानी सरकारी की

कमांड कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित होंगी बसें

योजना के तहत प्रदेश में पीपीपी मोड में जो बसें संचालित होंगी, उसका कंट्रोल पूरी तरह सरकार के पास होगा. स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा. ये कंट्रोल सेंटर इतना हाईटेक होगा, कि वहां से बस की स्पीड पर निगरानी रखी जा सकेगी. यदि ड्राइवर ओवर स्पिडिंग करते मिला तो उसे कंट्रोल सेंटर से चेतावनी दी जा सकेगी. इतना ही नहीं यदि वाहन चलते समय ड्राइवर को नींद आने लगती है और वह झपकी लेता है तो कंट्रोल सेंटर को पता चल जाएगा.

होल्डिंग कंपनी के साथ एमओयू करने वाले निजी ऑपरटर्स का पूरी तरह नियंत्रण उस रूट पर होगा. अभी कुछ राज्यों में केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 के तहत किया जा रहा है. मप्र में वर्ष 2005 तक संचालित

मप्र सड़क परिवहन निगम था इसी एक्ट के तहत संचालित था. अब बसों का संचालन मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याय 6 के तहत किया जाएगा. ऐसा करने वाला मप्र देश का पहला राज्य बनेगा.

पेज एक शेष ...

जिम्मेदारी से कार्य करें कलेक्टर और अधिकारी

तत्कालीन कलेक्टर अवधेश शर्मा, जिला विदिशा और विकासखंड बारीदा के लिए कलेक्टर अंशुल गुप्ता (प्रशिक्षण पर), तत्कालीन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, जिला झाबुआ और विकासखंड थांदा, मेघनगर, रामा व राणापुर के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान, जिला रतलाम और विकासखंड बाजना के लिए कलेक्टर राजेश बाथम, जिला अनूपपुर और विकासखंड पुष्पाराजगढ़ के लिए कलेक्टर हर्षुल पंचोली और जिला शहडोल और विकासखंडपाली के अधिकारियों को सम्मानित किया. जिला डिप्टी और आकांक्षी विकासखंड करंजिया, मेहेंदवानी व बजाग के लिए संयुक्त कलेक्टर भारतीय मेरवी तथा तत्कालीन कलेक्टर हर्ष सिंह, जिला खरगोन और विकासखंड भगवानपुर तथा क्षिरन्या के लिए कलेक्टर भाव्या मितल और तत्कालीन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, जिला राजगढ़ और विकासखंड जीरापुर के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित गुप्ता, जिला श्यापुर और विकासखंड श्यापुर, करालत तथा विजयपुर के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर तथा तत्कालीन कलेक्टर लोकेश कुमार जॉंजीड, जिला अलीराजपुर और विकासखंड कट्टीवाड़ा के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रखर सिंह, जिला छतरपुर और विकासखंड बवसावा के लिए सीईओ जिला पंचायत तपस्या परिहार तथा तत्कालीन कलेक्टर संदीप जीआरजी, जिला पन्ना और विकासखंड अजयगढ़ के लिए सीईओ जिला पंचायत उमराव सिंह, जिला सतना और विकासखंड मझगांव के लिए सीईओ जिला पंचायत संजाना जैन तथा तत्कालीन कलेक्टर अनुराग वर्मा तथा टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. सम्पूर्णांत अभियान ने शासन-प्रशासन की कार्य संस्कृति को नई दिशा दी है. डेटा आधारित मूल्यांकन और स्कॉरिंग प्रणाली तथा प्राथमिकताओं की स्पष्टता व पारदर्शिता से प्रशासनिक दक्षता और जन सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. इससे जिलों के बीच स्पर्धा प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिला है. नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा कि प्रदेश के समुच्च बड़ी चुनौती थी, परंतु प्रदेश के अधिकारियों के समर्पित प्रयासों से लक्षित सकेतों में सम्पूर्णांत प्राप्त करना संभव हुआ है.